

सोमनाथ मंदिर हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प: पीएम मोदी

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 मई को उन्हें एक बार फिर वहां जाने का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने इसे भारत की सभ्यता और आस्था की महानता का प्रतीक बताया और उन विभूतियों एवं वीरों को नमन किया जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सोमनाथ की रक्षा की और उसकी शान को पुनर्जीवित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में सोमनाथ पर लिखे अपने लेख को साझा करते हुए कहा कि यह अवसर हमें स्मरण कराता है कि इस पावन स्थल की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए देश की कई पीढ़ियों ने निरंतर संघर्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। समुद्र की लहरें हमें यह सिखाती हैं कि चाहे कितने भी तूफान क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है और यहां आने वाले श्रद्धालु

सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता, स्वाभिमान और अदम्य आस्था का प्रतीक



उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का अनुभव करते हैं, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। प्रधानमंत्री ने उन असंख्य विभूतियों का स्मरण किया जिन्होंने आक्रमणों के बीच भी सोमनाथ की रक्षा की। प्रधानमंत्री ने लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों से लेकर महाराज धारसेन चतुर्थ, भीम प्रथम, जयपाल, आनंदपाल, राजा भोज, कर्णदेव सोलंकी, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल सोलंकी, भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्य, विशालदेव वाघेला, त्रिपुरातक, महिपाल चूड़ासमा, राव खमार चूड़ासमा और पुण्यश्लोक

अहिल्याबाई होल्कर सहित अनेक नामों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सबने कठिन समय में भी भक्ति और परंपरा को जीवित रखा। उन्होंने वीर हमीराजी गोहिल और वीर वेणुदाजी भील जैसे पराक्रमियों को भी नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार बल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने समुद्र का जल हाथ में लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाषित साझा कर भारतीय सेना के शौर्य को किया नमन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सेना के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए जवानों का समर्पण हर देशवासी को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट साझा कर सेना के जज्बे की सराहना करते हुए लिखा कि "देश के मान-सम्मान की रक्षा के लिए भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम सभी देशवासियों को गौरवान्वित करता है। मां भारती के लिए मर-मिटने का उनका जज्बा

हर किसी को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने एक संस्कृत सुभाषित भी साझा किया- स्वधर्ममर्षि चावैश्वर्य न विकम्पितमुतर्हसि । धर्म्यादि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते।। इस सुभाषित का अर्थ है कि अपने कर्तव्य का बोध होने पर व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा या भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय की वेदी पर धर्म और मर्यादा की रक्षा हेतु किया गया संघर्ष ही एक योद्धा के लिए आत्म-कल्याण का सर्वोत्तम और सर्वाधिक गौरवशाली मार्ग है।

दुर्भाग्यवश वह इस सपने को साकार होते नहीं देख सके, लेकिन उनके विजन को केएम सुंगी ने आगे बढ़ाया और 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन समारोह में भाग लेकर

इसे ऐतिहासिक बना दिया, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया था। उन्हें अक्टूबर 2001 का वह समय याद है जब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व संभाला था।

ज्वलंत मुद्दा संपादकीय क्या राज्यपाल संवैधानिक मर्यादा से ऊपर हैं?



तमिलनाडु में चुनाव परिणाम आने के बाद उत्पन्न राजनीतिक स्थिति ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके साथ ही सरकार बनाने का दावा विजय राज्यपाल के समुच्च कर चुके हैं। कांग्रेस के समर्थन के बाद यह संख्या 113 तक पहुंच गई। बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। इसके बावजूद राज्यपाल द्वारा सरकार गठन के लिए आमंत्रित न करना केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि संवैधानिक परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख माना गया है, न कि राजनीतिक निर्णायक। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छा सर्वोपरि होगी।

वर्तमान में तमिलनाडु का मामला इसलिए अधिक गंभीर माना जा रहा है क्योंकि चुनाव नतीजों के मुताबिक दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली अन्य पार्टियों ने सरकार बनाने का दावा ही प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल को शायद ग्रहण का अवसर न देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से बाधित करने जैसा प्रतीत होता है। राज्यपाल यदि यह कहें कि पहले पूर्ण बहुमत साबित करें, तभी शपथ दिलाई जाएगी, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर विधानसभा में बहुमत परीक्षण की परंपरा का महत्व क्या रह जाएगा? पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में राज्यपाल और निर्वाचित सरकारों के बीच टकराव बढ़ा है। विपक्ष शासित राज्यों में विधेयकों को महीनों और कभी-कभी वर्षों तक लंबित रखना, सरकारों के प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप तथा राजनीतिक बयानबाजी ने इस पद की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल पद की कल्पना केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए की थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह पद कई बार राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनता दिखाई देता है।

सैयद जकी हैदर | सम्पादक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL.SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

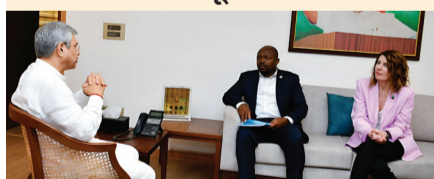
साक्षिप्त समाचार सुवेदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री



कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। भाजपा नेता सुवेदु अधिकारी को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक रूप से उनके नाम की घोषणा की। इस दौरान शाह ने मंच पर सुवेदु अधिकारी को माला पहनाकर गले लगाया और जीत की बधाई दी।

शपथ ग्रहण समारोह आज : सुवेदु अधिकारी शनिवार सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगड पंड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सुवेदु अधिकारी ने इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने नदीग्राम सीट से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की।

भारत में एआई इंप्रोस्ट्रचर, सर्वर, ड्रोन निर्माण में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा गूगल : वैष्णव



नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंप्रोस्ट्रचर, सर्वर और ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। वैष्णव ने सोशल मीडिया पंच एक्स पर गूगल के अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि कंपनी भारत में एआई इंप्रोस्ट्रचर के विकास के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्रों में भी अवसरों का आकलन कर रही है। वैष्णव ने कहा, "गूगल भारत में एआई इंप्रोस्ट्रचर और सर्वर तथा ड्रोन के निर्माण के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल देश में उपरते एआई इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इसी वर्ष अप्रैल में गूगल ने विशाखापत्तनम में अपने 15 अरब डॉलर के एआई हब की आधारशिला रखी थी। सरकार पहले से ही सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और एआई आधारित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठा रही है। गूगल की संभावित निवेश योजनाओं को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट के तीन संस्थापकों को गिरफ्तार किया



प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट के तीन संस्थापकों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा को धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएनए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है। दीपक सिंह और पृथ्वीराज सिंह को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उन्हें बेंगलुरु की अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल की गई है। विकास तनेजा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है। वे गिरफ्तारी तब हुई जब केंद्रीय एजेंसी ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई प्राथमिकियों का संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन गेमिंग

ममता बनर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल से 'मुख्यमंत्री' शब्द हटाने को तैयार नहीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई हैं। इस समय वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी उनकी पहचान "मुख्यमंत्री" के रूप में दर्ज है। इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्यपाल के निर्देश और विधानसभा भंग होने के बाद भी ममता बनर्जी का सोशल मीडिया पर "मुख्यमंत्री" पद का उल्लेख बनाए रखना संवैधानिक मर्यादाओं पर खलल खड़ा करता है। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक वर्गों में चर्चा तेज हो गई है। ममता बनर्जी पहले ही चुनाव परिणामों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि यह जनदेश नहीं बल्कि एक साजिश का परिणाम है और वह चुनाव नहीं हारी हैं। इसी कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से भी इनकार किया था। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद गुरुवार को राज्यपाल आरएन खे ने विधानसभा भंग करने का आदेश जारी किया।

देश में पेट्रोल की कीमतें लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर

एजेंसी। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमतें लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर बनी हुई हैं, जबकि मंत्रालय ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की लगभग 20 फीसदी ऊर्जा हॉर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिससे यह भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 40 फीसदी, एलपीजी का 90 फीसदी और प्राकृतिक गैस का 65 फीसदी हिस्सा मध्य-पूर्व से ही आयात करता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कच्चे तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर से बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि एलपीजी की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियों को हो रहे नुकसान के बावजूद, भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती करके एलपीजी उत्पादन बढ़ाकर, पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देकर और गैस की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करके उपभोक्तकों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत में पेट्रोल की कीमतें लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर बनी हुई हैं, जबकि दुनिया में अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की लगभग 20 फीसदी ऊर्जा हॉर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिससे यह भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 40 फीसदी, एलपीजी का 90 फीसदी और प्राकृतिक गैस का 65 फीसदी हिस्सा मध्य-पूर्व से ही आयात करता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कच्चे तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर से बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि एलपीजी की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियों को हो रहे नुकसान के बावजूद, भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती करके एलपीजी उत्पादन बढ़ाकर, पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देकर और गैस की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करके उपभोक्तकों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत में पेट्रोल की कीमतें

अमित शाह रविवार को देश में बाढ़ प्रबंधन, लू से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा

एजेंसी। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 10 मई को यहां एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें देश में संभावित बाढ़ और लू (होटवेव) की स्थिति से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्रालय के शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार बैठक में केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, संसाधनों की तैयारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा की जाएगी। बैठक में जान-माल के नुकसान को न्यूनतम रखने के उपायों पर विशेष जोर रहेगा। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 'समग्र

प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान संबंधी वैज्ञानिक प्रगति शामिल हैं। गृहमंत्री पिछले वर्ष आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति का भी आकलन करेंगे ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और विभिन्न गतिविधियों के समन्वित क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। बैठक के प्रमुख एजेंडों में उन्नत तकनीक और रियल-टाइम डेटा के जरिए बाढ़ पूर्वानुमान एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना, बाढ़ और लू जैसी एक साथ आने वाली आपदाओं से निपटने की तैयारी बढ़ाना, सामुदायिक जागरूकता एवं आपदा-रोधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा राहत समग्री और चिकित्सा तैयारियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना शामिल है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार, दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा



एजेंसी। बीजिंग। चीन ने अपने सैन्य तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई करते हुए दो पूर्व रक्षा मंत्रियों, वेई फेंगहे और ली शांगफू को संस्पेंडेड डेथ सेंटेंस (स्थगित मृत्युदंड) की सजा सुनाई है। सैन्य अदालत द्वारा सुनाया गया यह फैसला न केवल चीन के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। इन दोनों शीर्ष अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए मौत की सजा दी गई है, हालांकि कानून के प्रावधानों के तहत उन्हें दो साल की मोहलत दी जाएगी। यदि इस अवधि के दौरान उनका आचरण संतोषजनक रहता है और कोई नया गंभीर अपराध सामने नहीं आता, तो इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, जिसमें पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा पारा, कई राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्रों में शुक्रवार को आसमान साफ पारा। यहां का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे मौसम में कल के मुकाबले आज हल्की गर्मी रही। वहीं, देश के अन्य हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश और झारखंड में ओलावृष्टि, जबकि गुजरात में लू चलने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग केन्द्र के अनुसार शनिवार को भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। यहां का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा का रूख भी दक्षिण-पूर्व दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने की संभावना है। रविवार को भी यही स्थिति रहेगी और अधिकतम तापमान 37-39 जबकि न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। इसके अलावा, राजधानी में 11 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान, शाम से हवाओं की गति 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तक रहने के आसार हैं। हवा की वित्तीय अनियमितता या अनुशासनहीनता को बदरित करने के मूड में नहीं है, चाहे दोषी कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship for Lye Contact Karen . (9315755133 / ya_email_karen) angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का कार्यभार संभाला

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। जाने-माने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का पदभार शुक्रवार को संभाल लिया। लाहिड़ी ने सुमन बेरी की जगह ली है। आर्थिक नीति और सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले अशोक कुमार लाहिड़ी भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। नीति आयोग ने अशोक कुमार लाहिड़ी का उपाध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा जगत, सार्वजनिक संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उनका अनुभव, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में नीति आयोग के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। आयोग ने उनसे भारत के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक नीतियां पहलों को समर्थन देने में योगदान की अपेक्षा की है।



भारत-सिंगापुर आतंकवाद और सीमा पार अपराध के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारत और सिंगापुर ने आतंकवाद तथा सीमा पार अपराध के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की कड़ी निंदा करते हुए इसके खिलाफ 'जोरो टॉलरेंस' की नीति की बात दोहराई। भारत और सिंगापुर के बीच आतंकवाद एवं सीमा-पार अपराधों से निपटने पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पांचवीं बैठक 7 मई को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षा भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आतंकवाद-शोषी) डॉ. विनोद बहादुर और सिंगापुर के गृह मंत्रालय में उप सचिव (नीति) नियम शिंह चुन ने की। संयुक्त प्रेस विज्ञापित के अनुसार, भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के तौर पर आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। जेडब्ल्यूजी ने बैठक में सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहनशीलता' के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की। जेडब्ल्यूजी ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले और 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के निकट हुई आतंकवादी घटना की भी कड़े शब्दों में निंदा की। जेडब्ल्यूजी इस बात पर सहमत हुआ कि आतंकवाद का सामना करने के लिए निरंतर और व्यापक स्तर पर समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। इस संदर्भ में दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त कार्य समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और आतंकी समूहों का मुकाबला करने में सहयोग पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने सीमा पार के खतरों से निपटने के लिए सूचना साझाकरण को और प्रभावी तथा समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर सहमति जताई। बैठक में आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, कट्टरपंथ, आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे पारंपरिक एवं उभरते खतरों पर भी चर्चा हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद के खतरों के आकलन, साइबर अपराधों, नशीली पदार्थों की तस्करी और सीमा पार संगठित अपराध तथा आतंकवाद के गठजोड़ पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया और इन चुनौतियों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के एंटी-स्कैम सेंटर का भी दौरा किया। दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और धोखाधड़ी से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया तथा सूचना आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और समावेशी विकास के साझा उपयोग के माध्यम से सहयोग मजबूत करने की इच्छा जताई।

इंदौर-खंडवा राजमार्ग परियोजना 88 फीसदी पूरी, इस साल शुरू होगा यातायात

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बन रहे इंदौर-खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तेजाजी नगर-बलवाड़ा खंड पर चार लेन सड़क और तीन सुरंगों का निर्माण 88 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सरकार इसे इसी साल यातायात के लिए खोलने की तैयारी में है। इस परियोजना से घाटी क्षेत्रों में यात्रा समय घटकर मात्र एक घंटे रह जाएगा और दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भेरूघाट (575 मीटर), बैग्राम (480 मीटर) और चारल घाट (550 मीटर) सुरंगों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इन सुरंगों से घाटी मार्गों के प्रमुख ब्लैक स्पॉट स्थायी रूप से दूर होंगे और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। स्थानीय किसानों और चालकों ने कहा कि पहले मंडियों तक माल पहुंचाना जोखिम भरा था और संकरी दो-लेन सड़क पर हर यात्रा तनावपूर्ण होती थी। आज चौड़ी सड़क और सुरंगों से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या दूर होगी। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना पर 924.44 करोड़ रुपये की लागत आ रही है और इसके पूरा होने पर इंदौर से ओंकारेश्वर की यात्रा समय 2-3 घंटे से घटकर केवल 1 घंटे रह जाएगा। परियोजना में पर्यावरण और सुरक्षा उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आधुनिक जल निकासी प्रणाली, क्रैश बैरियर, सड़क सुरक्षा संकेतक, चर्चा जल प्रबंधन और हरित पट्टी के लिए वृक्षारोपण जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह कॉरिडोर न केवल धार्मिक यात्राओं बल्कि व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति देगा।

किसानों को राहत दिलाने के लिए कृषि मंत्रालय ने नेफेड- एनसीसीएफ को खरीद के लिए निर्देश

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएफएफडी) को लक्ष्य आधारित खरीद के निर्देश दिए। शुक्रवार को इस विषय को लेकर कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेफेड और एनसीसीएफ के साथ उपार्जन संबंधी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने दोनों एजेंसियों को किसानों के हितों को देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां बाजार भाव एमएसपी से नीचे है, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए। चौहान ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान को उसकी उपज का न्यायसंगत मूल्य दिलाना केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य में किसी भी स्तर की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में शिवराज सिंह ने कहा कि राजस्वार आवंटन के साथ-साथ जिला-स्तर पर उत्पादन, संभावित आवक और 25 प्रतिशत खरीद क्षमता का आकलन कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए ताकि उपार्जन का लक्ष्य वास्तविक जमीन पर हासिल हो सके। चौहान ने दलहन-तिलहन, विशेषकर चना, मसूर, उड़द और सरसों जैसी फसलों पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि जहां किसानों को एमएसपी से कम दाम मिल रहे हैं, वहां खरीद में तेजी लाना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को राज्यों में वास्तविक बाजार भाव की ताजा जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। चौहान ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य के निर्देश प्रतिक्रियाएं या स्थानीय प्रशासनिक अड़चनें किसानों से खरीद में बाधा बन रही हैं तो केंद्र सरकार सक्रिय समन्वय के जरिए उनका समाधान सुनिश्चित करेगी। चौहान ने कहा कि दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय लक्ष्य तभी सफल होगा, जब किसानों को यह भरोसा होगा कि जरूरत पड़ने पर उनकी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। चौहान ने नेफेड और एनसीसीएफ को निर्देश दिया कि वे उपार्जन को लेकर बेहतर काम करें, समस्याओं की सूची बनाकर समाधान सहित प्रस्तुत करें और शेष अवधि में खरीद प्रदर्शन में ठोस सुधार दिखाएं।



केजरीवाल और अन्य को दिल्ली आबकारी घोटाला से बरी किए जाने को लेकर सुनवाई टली

लोकतंत्र की शान नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 22 आरोपितों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को खारिज कर देकर नया सुनवाई का फैसला किया है, ऐसे में तीन एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाएंगे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 20 अप्रैल को दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि मैं इस आरोपितों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को खारिज कर देकर नया सुनवाई का फैसला किया है, ऐसे में तीन एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाएंगे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 20 अप्रैल को दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि मैं इस आरोपितों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को खारिज कर देकर नया सुनवाई का फैसला किया है, ऐसे में तीन एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाएंगे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 20 अप्रैल को दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि मैं इस आरोपितों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को खारिज कर देकर नया सुनवाई का फैसला किया है, ऐसे में तीन एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाएंगे।



उठाते हुए सुनवाई से हटने की मांग की थी। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग करते हुए कहा था कि जिस तरह से अब तक इस मामले में अदालती कार्यवाही हुई है, उससे उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। केजरीवाल ने कहा था कि बिना पक्ष सुने सेशन कोर्ट के आदेश को गलत बताया। उन्होंने कहा था कि 9 मार्च को जब उच्च न्यायालय में पहली सुनवाई हुई, तो वहां 23 में से एक भी आरोपित मौजूद नहीं था। कोर्ट में सिर्फ सीबीआई मौजूद थी। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहली ही सुनवाई में बिना दूसरी पक्ष की दलीलें सुने यह कह दिया कि 'प्रथम दृष्ट्य' सेशन कोर्ट का आदेश गलत लगता है। बिना रिकॉर्ड मंगवाए और बिना दलीलें सुने कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंच गया।

भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने की तैयारी में

लोकतंत्र की शान नई दिल्ली। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के दौरान भारत 2026 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही भारत ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंस्ट्रुमेंटल रिवोल्यूशन (पार्ट एनआईआर) के तहत एमएसएमई सहयोग के लिए एक नए एजेंडे का भी नेतृत्व कर रहा है। भारत की अध्यक्षता के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को तीन एएसएमई कार्य समूह बैठकों और पहली ब्रिक्स एमएसएमई फोरम आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहली एएसएमई कार्य समूह बैठक 24 अप्रैल को ऑनलाइन हुई, जिसका मुख्य विषय एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुंच रहा। इस वैबिनार में ब्रिक्स सदस्य देशों ने सक्रिय भागीदारी की। यह मंच एमएसएमई वित्तपोषण से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर अनुभव और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम बना। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि एमएसएमई आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, नवाचार और समावेशी विकास के प्रमुख आधार हैं। चर्चा के दौरान समान विकास संबंधी चुनौतियों



उपलब्ध न होने जैसी लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया। बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि ऋण अंतर को कम करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाते की जरूरत है। इसमें वित्तीय समावेशन बढ़ाना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और एमएसएमई को ऋण क्षमता को मजबूत बनाना शामिल है। बैठक में यह भी कहा गया कि एमएसएमई वित्त को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने, नवाचार-आधारित वित्तीय तंत्र को बढ़ावा देने और सहयोगी इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है। चर्चा के दौरान समान विकास संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे ब्रिक्स देशों के बीच नीतिगत अनुभवों का आदान-प्रदान भी हुआ। साथ ही सभी देशों ने मजबूत, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एमएसएमई क्षेत्र विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। भारत पहले ही जापान, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ समझौते कर चुका है, जिनका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। एमएसएमई क्षेत्र भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है।

आदिवासियों की जमीन कब्जाने की कोशिशों के खिलाफ किसान सभा ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, प्रशासन ने दिया जांच का निर्देश

लोकतंत्र की शान कोरबा। कोरबा जिले में भैरमा तहसील अंतर्गत ग्राम पतरापाली के आदिवासी किसानों के जमीन को कुछ अज्ञात गैर आदिवासियों द्वारा बेनामी खरीद के जरिए कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ गांव के लोगों ने आज यहां ताबरेन चौक से रैली निकालकर जिलाधीश कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने किया। डिप्टी कलेक्टर टी आर भारद्वाज ने किसानों की समस्या को सुना और जापान लेते हुए जांच करने हेतु गांव में शिविर लगाने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पतरापाली एक आदिवासी बहुल गांव है और लगभग सभी आदिवासी या तो निरक्षर है या बहुत कम पढ़े लिखे हैं। उन्हें भूमि



के निवासी हैं। खेती-किसानी ही इनकी आजीविका का साधन है और अपने पूर्वजों से प्राप्त जमीन पर वे खेती कर रहे हैं। मामला तब गंभीर हो गया, जब ऐसे ही एक मामले में एक गैर-आदिवासी ने सगे भाईयों मंगल सिंह और भूखन लाल पिता लोहरी को उसकी जमीन से बेदखल करके और उस जमीन पर घेरा डालकर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल करके और आशंका से डरे हुए उन्हें बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। वे इन लोगों को पहचानते तक नहीं



है। इन ग्रामीणों ने बताया कि वे बाहरी लोग वर्ष 1990 में ही उनके पूर्वजों से उनकी जमीन खरीदने का दावा कर रहे हैं। मामला तब गंभीर हो गया, जब ऐसे ही एक मामले में एक गैर-आदिवासी ने सगे भाईयों मंगल सिंह और भूखन लाल पिता लोहरी को उसकी जमीन से बेदखल करके और उस जमीन पर घेरा डालकर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल करके और आशंका से डरे हुए उन्हें बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रशांत झा, जिला सचिव दीपक

होना बताया जा रहा है, जबकि भूमि पर मूल भूस्वामी अभी तक काबिज है। ये सभी भूमि अंतरण बेनामी है और अवैध है, क्योंकि आदिवासी भूमि का किसी भी गैर-आदिवासी को अंतरण नहीं हो सकता। प्रशासन ने शिकायतों की जांच करने के लिए गांव में शिविर लगाकर भूमि स्वामित्व का निराकरण करने के लिए संबंधित तहसीलदार और पटवारी को निर्देश दिए हैं। किसान सभा और सीटू ने आदिवासी किसानों के पक्ष में सकारात्मक कार्यवाही न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने आशंका जताई है कि केवल पतरापाली ही नहीं, आसपास के अन्य गांवों में भी आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए ऐसे बेनामी फर्जी सौदे हुए होंगे, इसलिए इस क्षेत्र के गांवों में शिविर लगाकर वास्तविक भूमि स्वामित्व का सत्यापन किए जाने की जरूरत है।

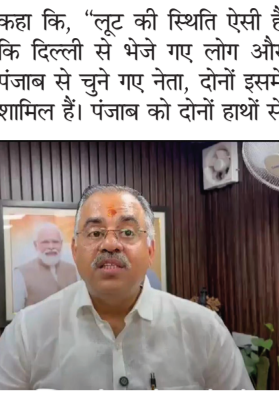
यौन अपराधों पर एनसीडब्ल्यू सख्त, पोक्सो मामले में पैरोल न देने की सिफारिश

लोकतंत्र की शान नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषी के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए अपराधियों को पैरोल दिए जाने पर गहरी चिंता जताई है। आयोग के अध्यक्ष विजया रघाटकर ने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार को सिफारिश भेज कर रेप, गैंगरेप, गंभीर यौन उत्पीड़न और पोक्सो जैसे मामलों में दोषियों को पैरोल न देने की मांग की जाएगी। अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि नरसरापुर-भोर की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आयोग ने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों

के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, जांच और ट्रायल में कानूनी विशेषज्ञों की मदद से बेहतर समन्वय, सबूतों की जांच, गवाहों के बयान और जांच प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने के लिए अलग तंत्र, रेप और पोक्सो मामलों के आदान अपराधियों पर कड़ी निगरानी शामिल है। आयोग ने यह भी कहा कि पोक्सो और अन्य यौन अपराधों में बार-बार शामिल होने वाले आरोपितों पर पुलिस की लगातार निगरानी होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर अच्छे व्यवहार के लिए बांड भ्रवाने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। आयोग ने जांच, सबूतों की जांच और गवाहों के बयान की प्रक्रिया को समयबद्ध और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया है। आयोग ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों का मकसद महिलाओं और बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित माहौल बनाना और पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाना है।

आआपा की सरकार पर भाजपा का आरोप, पंजाब को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है

लोकतंत्र की शान नई दिल्ली। पंजाब की राजनीति में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी (आआपा) के पिशाचा साधते हुए कहा कि पंजाब में साफ-सुथरी राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की सच्चाई अब सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग ईमानदारी के प्रमाणपत्र बांटते थे, आज उनके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। तरुण चुग ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पंजाब की जनता ने बदलाव के नाम पर आआपा को मौका दिया था लेकिन आज राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। राज्य में माफिया मजबूत हुए हैं और भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में फैल चुका है। उन्होंने



लूटा जा रहा है। 'एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की वंदे मातरम पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, "वंदे मातरम 150 वर्षों से अधिक समय से स्वतंत्रता सेनानियों की घोषणा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक नारे के समान था। जो लोग वंदे मातरम को मौका दिया था लेकिन आज राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। राज्य में माफिया मजबूत हुए हैं और भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में फैल चुका है। उन्होंने

राहुल गांधी बोले- कोई और पार्टी भाजपा को नहीं हरा सकती, सिर्फ कांग्रेस ही उसे हराएगी

लोकतंत्र की शान नई दिल्ली: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोई और पार्टी भाजपा को नहीं हरा सकती, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही भाजपा एवं नरेंद्र मोदी को हरा सकती है और हराएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित सद्भाव यात्रा में शामिल होने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा द्वारा चुनाव आयोग की मदद से चुनावों में की जा रही धांधली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों में चोरी कर जीत हासिल कर रही है; उसने हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में भी चोरी की है। भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर चुनाव चोरी करने की व्यवस्था बना ली है; मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और पूरी नौकरशाही भाजपा के नियंत्रण में काम कर रही है। भाजपा सोचती है कि उसका शासन नहीं जाएगा, लेकिन उसके जाने का समय आने वाला है। जनता समझ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं, वह यह भी समझ गई है कि देश की संपत्ति अजानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हवाले की जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कितने भी चुनाव चोरी कर लें, आज जनता में मोदी सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है और अंत में उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और वे टिक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी



ने कहा कि देश में सिर्फ दो राजनीतिक विचारधाराएं हैं - एक तरफ आरएसएस की नफरत एवं बंटवारे की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस की मोहब्बत एवं एकता की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का डर दिखाती है, लेकिन कांग्रेस इनसे नहीं डरती। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस भाजपा को हराएगी। इसके बाद नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने देश के लोकतांत्रिक सिस्टम और बाबा साहेब डॉ भीम राव अंबेडकर के संविधान पर आक्रमण किया है।

बांग्लादेश पहुंचे इंडियन ओशन शिप का शानदार स्वागत

लोकतंत्र की शान चट्टोग्राम। भारतीय नौसेना का इंडियन ओशन शिप (आईओएस) 'सागर', जिसे आईनएसएस 'सुनयना' के रूप में तैनात किया गया है, अपनी क्षेत्रीय समुद्री यात्रा के दौरान बांग्लादेश की चट्टोग्राम बंदरगाह पहुंचा। यह दौरा भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने वाली 'महासागर' पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे दोनों देशों के रिश्तों एवं आपसी विश्वास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ाना है। इस मिशन में 16 मित्र देशों के नौसैनिक शामिल हैं, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (पूरी दुनिया एक परिवार है) के आदर्श को साझा करते हैं। बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग



ने 8 मई को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा यह उच्च-स्तरीय बंदरगाह दौरा, जो 'आईओएस सागर 2026' बहुदलीय तैनाती का एक हिस्सा है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच अटूट साझेदारी का प्रमाण है। यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। बांग्लादेश के जलक्षेत्र में इस जहाज का स्वागत बीएनएस अली हैदर (एफ17) द्वारा किया गया और उसे एस्कॉर्ट करते हुए बंदरगाह तक पहुंचाया गया। भारतीय उच्चायोग ने कहा आईओएस सागर के कमांडिंग ऑफिसर कई

पेशेवर 'क्रॉस-डेक विजिट' में हिस्सा लेंगे। कू सदस्य बीएनएस इस्सा खान प्रशिक्षण परिसर और बांग्लादेश नौसेना अकादमी का दौरा भी करेंगे, जिससे नौसेना प्रशिक्षण की कार्यप्रणालियों की गहरी समझ विकसित होगी और आपसी क्षमता निर्माण के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के बीच एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच भी होगा, जो दोनों पक्षों के बीच साझा 'एस्पिरिट डी कॉर्पो' (आपसी भाईचारे) को उजागर करेगा। बता दें कि आईओएस सागर 2026 मिशन के दूसरे संस्करण की शुरुआत 2 अप्रैल को मुंबई से हुई थी। चट्टोग्राम पहुंचने से पहले यह जहाज माले (मालदीव), फुकुत (थाईलैंड), जंगल (इंडोनेशिया), सिंगापुर और यूंगून (व्यामोर) जैसे बंदरगाहों का दौरा कर चुका है। यह मिशन मई के मध्य तक कोच्चि पहुंचकर समाप्त होगा।

संक्षिप्त समाचार

जिस जहाज पर हंतावायरस फैला, उस पर 2 भारतीय, अब तक 3 की मौत



प्राया। अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप MV हॉंडियस पर 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यह वही शिप है, जिस पर हंतावायरस फैला है। BBC के मुताबिक अब तक जहाज पर हंतावायरस संक्रमण के पांच मामलों की पुष्टि हुई है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में भर्ती हंतावायरस मरीज का इलाज कर रही डॉक्टर करिन एलेन वेल्डकैप ने कहा कि यह वायरस कोरोना जैसा नहीं है। उन्होंने AFP से बातचीत में कहा कि हंतावायरस का इंसान से इंसान में फैलना आसान नहीं है। इसका ट्रॉसमिशन कोरोना की तुलना में काफी मुश्किल है। डच फ्लैग वाला यह जहाज स्पेन जा रहा है। यह 10 मई तक स्पेन के कैनरी आइलैंड तक पहुंच सकता है, जहां जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों की जांच होगी। WHO ने कहा कि घटना गंभीर है, लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए खतरा कम माना जा रहा है। डॉक्टर करिन एलेन वेल्डकैप ने कहा, ऐसे मामलों में संक्रमित मरीजों को अलग आइसोलेशन रूम में रखा जाता है। ट्रेंड स्टॉप उनकी देखभाल करता है। मरीजों को तब तक आइसोलेशन में रखा जाता है, जब तक उनमें लक्षण दिखाई देते हैं। हालात सुधरने के बाद उनका टेस्ट किया जाता है। अगर रिपोर्ट नैगेटिव आती है तो आइसोलेशन हटाया जा सकता है। हावर्ड के प्रोफेसर एलन ने बताया कि हंतावायरस से संक्रमित लोगों को 40 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है, क्योंकि इसका इन्क्यूबेशन पीरियड लंबा होता है। शरीर में वायरस के चुसने से लेकर पहले लक्षण दिखने के बीच के समय को इन्क्यूबेशन पीरियड कहते हैं। डॉक्टर के मुताबिक, अभी यह साफ नहीं है कि वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में कब तक रह सकता है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसियस ने कहा कि हंतावायरस का इन्क्यूबेशन पीरियड छह हफ्ते तक हो सकता है। इसलिए आगे भी नए मामले सामने आने की आशंका बनी हुई है।

ट्यूनीशिया में पत्रकार जियेद हेनी को एक साल की जेल

ट्यूनिस्। ट्यूनीशिया की एक अदालत ने चर्चित पत्रकार जियेद हेनी को न्यायपालिका की आलोचना करने के मामले में एक वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी को लेकर बहस तेज हो गई है। जियेद हेनी को पिछले महीने उस समय हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने एक लेख में न्यायपालिका के एक फैसले की आलोचना की थी। उनके वकील नफा लारी बी ने अदालत के फैसले को “कठोर” बताते हुए कहा कि यह ट्यूनीशिया में स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर बढ़ती पाबंदियों को और मजबूत करता है। सजा सुनाए जाने से एक दिन पहले हेनी ने जेल से अपने परिवार के माध्यम से एक पत्र जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा कि वह इस मामले में किसी भी फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे क्योंकि वह इस मुकदमे को वैध नहीं मानते। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों और पत्रकार संगठनों का कहना है कि राष्ट्रपति केस सईद के सत्ता केंद्रीकरण के बाद देश में स्वतंत्र आवाजों पर दबाव लगातर बढ़ा है। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति सईद ने निवर्तित संसद को भंग कर दिया था और बाद में अध्यादेशों के जरिए शासन शुरू किया। इसके बाद 2022 में उन्होंने सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल को भी भंग कर कई न्यायाधीशों को पद से हटा दिया था। विपक्षी दलों ने तब आरोप लगाया था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हुई है। हालांकि राष्ट्रपति सईद इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है और देश में स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित है। उल्लेखनीय है कि 2011 में ट्यूनीशिया में हुए जनआंदोलन के बाद अभिव्यक्ति की आजादी में काफी विस्तार हुआ था और इसी आंदोलन ने “अरब स्प्रिंग” की शुरुआत की थी लेकिन हाल के वर्षों में विपक्ष नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कारोबारियों की गिरफ्तारी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

एमपी और यूपी में आंधी-बारिश से 10° तक घटा तापमान

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान से सटे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और गंगा से सटे बंगाल के इलाकों में आज आंधी-बारिश का अलट है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई जिलों में भी अगले 7 दिन तक भारी बारिश होगी। शुक्रवार को एमपी में आंधी बारिश के बाद तापमान 34°C तक पहुंच गया। यूपी में भी बारिश से राहत रही। 7 दिन पहले जिस बाढ़ में तापमान 47.6°C था, वह 7 मई को 38°C तक पहुंच गया। हालांकि, गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मी और उमस वाला मौसम बना हुआ है। गुजरात का राजकोट देश में सबसे गर्म रहा, यहां का तापमान 42.9°C दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला प्रशासन ने निजी कोचिंग संस्थानों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच क्लासेस रोकने को कहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि क्लासेस सुबह-शाम या ऑनलाइन/डिजिटली लगाई जाएं। उत्तराखंड में आज भी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। केदारनाथ में भी गुरुवार को ताजा बर्फबारी हुई।

नासिक टीसीएस केस- मुख्य आरोपी निदा खान हिरासत में, यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाएं अहत करने के आरोप

नासिक। नासिक TCS केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी निदा खान को गुरुवार रात छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया। निदा पर सेक्सुअल हैरसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप हैं। इससे पहले 2 मई को नासिक कोर्ट ने निदा की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज की थी। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि आरोप गंभीर हैं और उनसे कस्टडी में पहुंचाओ जरूरी है। इस दौरान निदा फरार चल रही थी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजाय मिसर ने बताया था कि निदा खान इस केस की मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। FIR के अनुसार, निदा पर आरोप है कि उसने महिला कर्मचारियों को बुर्का पहनने की सलाह दी थी। मामले की जांच नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 9 FIR दर्ज हुई हैं, जो महिला कर्मचारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ी हैं। SIT ने इस मामले में अब तक एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। निदा ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अपनी प्रेनेसी का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया था। मामले पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (TCS) ने पिछले महीने बयान में कहा था कि कंपनी किसी भी तरह के हैरसमेंट और जबरदस्ती के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है।

यूक्रेन ने रूस में विजय दिवस समारोह से पहले की ड्रोन हमलों की बौछार

एजेंसी, मॉस्को

रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी 2022 से शुरू यह युद्ध अब वैश्विक कूटनीतिक और आर्थिक तनाव का केंद्र बन गया है। रूस में नौ मई को विजय दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए रूस ने एकतरफा सैन्य विराम की घोषणा की है। यह 8 मई आधी रात से प्रभावी होगा। यूक्रेन ने गुरुवार रात रूस पर ड्रोन हमलों की बौछार की है। तास न्यूज एजेंसी और मॉस्को टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने दावा किया है कि हमले के लिए दाग गए यूक्रेन के 347 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाने के मकसद से ड्रोन की बौछार की। इसे युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है। इससे पहले मार्च में यूक्रेन ने 389 ड्रोन लॉन्च किए थे।



रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को समेत कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा। गुरुवार दिन में भी यूक्रेन ने कई और ड्रोन भेजे। यह मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। इसका असर राजधानी के हवाई यातायात पर भी पड़ा। मॉस्को के तीन बड़े एयरपोर्ट्स में, डोमोडेडोवो और वनूकोवो से करीब 100 ड्रॉनों रत या देर से संचालित हुईं। महत्वपूर्ण है कि रूस के सैन्य विराम की घोषणा से पहले यूक्रेन ने भी मंगलवार आधी रात से हमले रोकने की बात कही थी। यूक्रेन का दावा है कि उसके दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में रूसी ड्रोन हमले में तीन बच्चों समेत नौ लोग घायल हो गए। रूस ने रातभर में 102 ड्रोन दागे। उनमें से 92 को मार गिराया। रूस के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि विजय दिवस समारोह शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। 9 मई को मॉस्को में मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवाएं

भी बंद रहेंगी। इस बार परेड में टैंक, मिसाइल और भारी सैन्य उपकरण नहीं दिखेंगे। मंत्रालय ने इसकी वजह मौजूदा सुरक्षा स्थिति बताई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि स्थिति जटिल है। बावजूद इसके विजय दिवस पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। वहीं, रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर विजय दिवस समारोह में कोई बाधा डालने की कोशिश हुई तो कीव पर बड़े स्तर का जवाबी हमला किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि जवाबी कार्रवाई की संभावना को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कीव में मौजूद विदेशी दूतावासों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी एहतियातन अपने कार्यालय खाली करने की सलाह दी है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने सेंट पीटर्सबर्ग में आम नागरिकों की जगहों पर ड्रोन हमले करने के लिए लातवियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। यह आरोप तब लगाया गया, जब लातविया ने कहा कि रूस की तरफ से कई ड्रोन उसके इलाके में घुस आए। लातवियाई अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार तड़के दो ड्रोन उनके इलाके में गिर गए।

महाराष्ट्र बोर्ड दसवीं का रिजल्ट घोषित 92.90 प्रतिशत विद्यार्थी सफल

एजेंसी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की आयोजित दसवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष कुल 92.90 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए हैं। सबसे अधिक परिणाम कोकण विभाग का रहा, जहां 97.62 प्रतिशत छात्र पास हुए, जबकि सबसे कम परिणाम छत्रपति संभाजीनगर विभाग का 88.41 प्रतिशत दर्ज किया गया।



राज्य मंडल के अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी ने पत्रकार परिषद में परिणाम घोषित किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रनजीतसिंह देओल, शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, परीक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के पुणे, मुंबई, नाशिक, लातूर, अमरावती, नागपुर, कोकण, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजीनगर समेत नौ विभागीय मंडलों के माध्यम

नेपाल में बस्तियां खाली कराए जाने का विरोध, देश भर में भूमिहीनों का विरोध प्रदर्शन

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बस्तियां खाली कराए जाने के बाद देशभर के भूमिहीन लोग सड़क पर उतर आए हैं। काठमांडू की 16 बस्तियों से नौ दिनों में 15 हजार से अधिक लोग विस्थापित किये जा चुके हैं। सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर बने अनधिकृत बांघों को हटाने के लिए जारी 35 दिन की नोटिस के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे हैं। काठमांडू से नौ दिन पहले शुरू हुआ बस्ती खाली कराने का अभियान अब पूरे देश में चलाने की तैयारी है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बस्तियां खाली कराए जाने के विरोध में भूमिहीन तथा अल्पव्ययिष्ठ लोगों में शुकवार को बुटवल में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार पहले वास्तविक भूमिहीन



और अल्पव्ययिष्ठ बसोबासियों की पहचान करे और पिछली सरकारों के दौरान भूमि आयोग की तय व्यवस्था के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कर लालुजुर्जा (मालिकाना प्रमाणपत्र) उपलब्ध कराए। भूमिहीन संघर्ष समिति के संयोजक खगेन्द्र पौडेल ने कहा कि सरकार ने बिना किसी तैयारी और विकल्प के डोजर चलाकर लोगों में आतंक फैलाया है। आज ही मकवानपुर जिले के हेटौडा में भी संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर सुकुमबासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। थाना भर्याड से शुरू हुई रैली के प्रतिभागियों ने

प्रमुख जिला अधिकारी और हेटौडा के मेयर को ज्ञापन पत्र सौंपा। इसी तरह बर्दिया जिला मुख्यालय गुलरिया में भूमिहीन, मुक्त कर्मैया और अल्पव्ययिष्ठ बसोबासियों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रदेश के वन मंत्रालय ने 15 दिन की नोटिस जारी कर लोगों को उजाड़ने की कोशिश की है। बर्दिया की आठों स्थानीय पालिकाओं के प्रमुखों ने बस्तियां खाली कराने संबंधी नोटिस का विरोध किया। इधर काठमांडू के माइतीघर मण्डला में भी भूमिहीन, अधिकारकर्मी और अन्य संगठनों ने अलग-अलग प्रदर्शन किए हैं। भूमिहीनों को जो जबरन विस्थापित

किए जाने के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार भूमिहीनों पर अमानवीय दमन कर “श्वेत आतंक” फैला रही है।

आज ही रुपन्देही जिले के मोतिपुर क्षेत्र के निवासी भी सरकार द्वारा डोजर चलाकर आतंकित किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि भूमिहीनों के पुनर्वास और कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए बिना यदि बस्तियां खाली कराई गईं, तो वे प्रतिरोध करेंगे। सरकार पर बिना तैयारी लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाते हुए सुनसरी जिले के धरान में आगे सुबह से ही प्रदर्शन जारी है। नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण समाज द्वारा आयोजित जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि यदि धरान की बस्तियां हटाने की कोशिश की गई तो उसका विरोध किया जाएगा।

शांति प्रयासों के बीच तेहरान से लेकर होर्मुज तक तनाव अमेरिका ने किया हवाई हमला, ईरान ने भी दिया जवाब

एजेंसी, तेहरान/वॉशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे शांति प्रयासों के बीच तेहरान से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य तक तनाव बढ़ गया है। ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिकी सेना ने तटीय जलक्षेत्र में एक ईरानी तेल टैंकर और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह के पास दूसरे जहाज को निशाना बनाया। इसके अलावा दक्षिणी ईरान के बंदर खमीर, सिरिक और केशम द्वीप के नागरिक इलाकों में अमेरिका की वायुसेना ने हवाई हमला किया। ईरान का दावा है कि उसने दुश्मन को माफूल जवाब दिया। अल जजीरा, इरान और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना की संट्रल कमांड (सैंटकॉम) ने कहा कि उसने आत्मरक्षा के लिए यह कदम उठाया। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में उसके नौसैनिक बलों को आत्मरक्षा के लिए एक कदम उठाया। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में उसके नौसैनिक बलों से हमला किया। इसलिए हमला करने के लिए जिम्मेदार ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी



ठिकानों पर हुए हमलों को “प्यार भरा थपड़” बताया है। उन्होंने कहा कि “ सैन्य विराम जारी है। यह प्रभावी है।” उन्होंने पत्रकारों से कहा: “ ईरान ने हमसे पंगा लिया। हमने उन्हें उड़ा दिया।” ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। रिपोर्टों में कहा गया कि ईरान युद्ध खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार करने की बात तो कह रहा है पर वह होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण औपचारिक रूप से स्थापित करने की भी कोशिश कर रहा है। शिपिंग इंटीलिजेंस फर्म ‘लॉयड्स लिस्ट’ का

कहना है कि जलडमरूमध्य अब बंद हो गया है। ईरान का कहना है कि उसने हाल ही में एक नई एजेंसी बनाई है। वह यहां से गुजरने वाले जहाजों को मंजूरी देने का काम करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। इन कूटनीतिक प्रयासों के बीच, अंतरराष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेट कूड ऑथल की कीमतें गुरुवार को लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रही। युद्ध शुरू होने से पहले यह कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल थी। तेहरान के साथ ताजा तनाव के बीच फ्लोरिडा के टैम्पा स्थित सेंट्रल कमांड ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि ताजा हवाई हमला आत्मरक्षा के लिए किया गया। विदेशमंत्री मार्को रुबियो ने पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका आत्मरक्षा करने में पीछे नहीं हटेगा। बताया गया है कि तेहरान में रात को कई जगह धमाके सुने गए। एयर डिफेंस सिस्टम को चालू किया गया। इस दौरान ईरान की राजधानी में दो धमाके हुए। ईरान के दक्षिणी इलाके के मीनाब शहर में यमनर ने घर से बाहर आकर एक नौसैनिक अड्डे पर हुए हमलों की पुष्टि की।

इंदौर-खंडवा राजमार्ग परियोजना 88 फीसदी पूरी, इस साल शुरू होगा यातायात

एजेंसी, नई दिल्ली

मध्य प्रदेश के बन रहे इंदौर-खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तेजाजी नगर-बलवाड़ा खंड पर चार लेन सड़क और तीन सुरंगों का निर्माण 88 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सरकार इसे इसी साल यातायात के लिए खोलने की तैयारी में है। इस परियोजना से घाटी क्षेत्रों में यात्रा समय घटकर मात्र एक घंटे रह जाएगा और दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग पर भेरूवाट (575 मीटर), बैग्राम (480 मीटर) और चोरल घाट (550 मीटर) सुरंगों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इन सुरंगों से घाटी मार्गों के प्रमुख ब्लैक ध्यान दिया गया है। आधुनिक जल नििकासी प्रणाली, क्रेश बैरियर, सड़क सुरक्षा संकेतक, वर्षा जल प्रबंधन और हरित पट्टी के लिए वृक्षारोपण जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह कॉरिडोर न केवल धार्मिक यात्राओं बल्कि व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति देगा।



तनावपूर्ण होती थी। अब चौड़ी सड़क और सुरंगों से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या दूर होगी। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना पर 924.44 करोड़ रुपये की लागत आ रही है और इसके पूरा होने पर इंदौर से ऑंकारेश्वर की यात्रा समय 2-3 घंटे से घटकर केवल 1 घंटे रह जाएगा। परियोजना में पर्यावरण और सुरक्षा उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आधुनिक जल नििकासी प्रणाली, क्रेश बैरियर, सड़क सुरक्षा संकेतक, वर्षा जल प्रबंधन और हरित पट्टी के लिए वृक्षारोपण जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह कॉरिडोर न केवल धार्मिक यात्राओं बल्कि व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति देगा।

सुप्रीम कोर्ट बोला- मंत्री शाह को ऐसे कमेंट्स की आदत

एजेंसी, भोपाल

सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुर्देशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन स्वीकृति देने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कई शब्दों में कहा- “Enough is enough (बस बहुत हुआ), अब हमारे आदेश का पालन कीजिए।” कोर्ट ने कहा- यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था: सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि शायद उनके बयान को गलत समझा गया और वे महिला अधिकारी की प्रशंसा करना चाहते थे तो सीजेआई सूर्यकांत ने इसे सिर से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा- यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। एक राजनता के तौर पर उन्हें अच्छी तरह पता है कि किसी महिला अधिकारी की प्रशंसा कैसे की जाती है। कोर्ट ने SIT की स्टेट्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि मंत्री को इस तरह के कमेंट



करने की आदत है। इंदौर के पास रायकुंडा गांव में दिया था विवाद बयान: यह विवाद पिछले साल भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई क्रॉस-बॉर्डर सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ था। कर्नल सोफिया कुर्देशी ने इस ऑपरेशन की मीडिया ब्रीफिंग की थी। इसके बाद महुं के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कहा था, “जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी ही एक बहन को भेजा।” इस बयान को कर्नल कुर्देशी के धर्म

कर्नल सोफिया मामले में एमपी सरकार को फटकार, कहा- बहुत हुआ, आदेश का पालन करें

से जोड़कर देखा गया, जिसकी हर तरफ निंदा हुई। मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन्होंने यहां तक कहा था- “अदालत के आदेश को लागू करने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं नर्क भी एक कर दूंगा।” एसआईटी ने सरकार से केस चलाने की परमिशन मांगी, दो हफ्ते से लंबित: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर मंत्री के खिलाफ केस चलाने (अभियोजन) के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है, जो पिछले दो हफ्तों से लंबित है। मंत्री शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196 (1) (b) और 197(1)(c) के तहत मामला दर्ज है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने और समूहों की हालत गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया है।

सगे भाइयों ने इकलौती बहन को घर गिफ्ट किया

एजेंसी, लुधियाना

लुधियाना में सगे भाइयों ने इकलौती बहन को 175 गज का घर गिफ्ट कर दिया। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। भाइयों ने सरप्राइज तरीके से बहन को ये गिफ्ट दिया। वह ढोल बजाते हुए बहन को वहां ले गए। जब उन्होंने नेम प्लेट से कागज हटाया तो अपना नाम लिखा देकर बहन रो पड़ी। बहन शादीशुदा है। भाइयों का कहना है कि पिता के निधन के बाद बहन हमेशा उनके साथ खड़ी रही। इसलिए अपने घर के नजदीक ही मकान बनाकर दिया। बहन को घर गिफ्ट करने वाले दोनों भाई एक्टिंग करते हैं। एक भाई बिग बॉस के सीजन 10 में कॉमनर कंटेस्टेंट के तौर पर भी हिस्सा ले चुका है। अमर देवगन और देव देवगन ने बताया कि उनकी बहन मनप्रीत कौर की शादी 2011 में लुधियाना में ही हुई। मनप्रीत के पति हॉल लॉन डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं। वैसे तो, बहन के पास पहले से ही 2 प्रॉपर्टी हैं लेकिन वह चाहते थे कि मायके से भी कुछ नया मिले। इसी वजह से



175 गज में बना, कीमत करीब 50 लाख, सरप्राइज देख फूट-फूटकर रोई

उन्होंने तय किया कि बहन को कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दें।

पहले ब्रेजा गिफ्ट की, 5 साल से प्लानिंग कर रहे थे: भाई देव ने बताया कि इससे पहले रक्षाबंधन पर उन्होंने बहन मनप्रीत को एक्टवा गिफ्ट दी थी। फिर 19 मई 2025 को बहन की मैरिज एनिवर्सरी थी। जिसमें उन्होंने बहन को ब्रेजा कार गिफ्ट की थी। जिसके बाद उन्होंने बहन को 175 गज का घर गिफ्ट करने की प्लानिंग की। हालांकि इसकी प्लानिंग वह 5 साल से कर रहे थे। यह घर जिंदगी भर अब बहन के साथ रहेगा।

बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार: बंगाली अस्मिता,क्षेत्रीय गौरव और स्थानीय नेतृत्व को प्रमुखता -शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ -समग्र व्यापक विश्लेषण



लोकतंत्र की शान

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 8 मई 2026 का दिन एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के रूप में दर्ज हो गया,जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक में शुभेंदुअधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया,विधायक दल की बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष ने सुवेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा। विधायकों को को पूरा मौका दिया गया कोई दूसरा नाम नहीं आया था ऐसा पर्यवेक्षक ने प्रेस में बताया।प्रस्ताव का समर्थन आठ से अधिक विधायकों सहित कई विधायकों ने किया और सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया जिसकी घोषणा पर्यवेक्षक अमित शाह ने की तथा माला पहनकर उनको गले लगाया, वे अपने पास गृह विभाग रख सकते हैं। संभवतः भाजपा दो उपमुख्यमंत्री वाला मॉडल अपना सकती है,जिसमें एक संभवतः रूपा गांगुली व दूसरा दार्जिलिंग क्षेत्र से बनाने की संभावना है और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश होगी। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनांनी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि मुख्यमंत्री चुनकर एक ऐसे राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कर दी है,जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस के प्रभुत्व वाले बंगाल में भाजपा का सत्ता तक पहुंचना केवल एक चुनौती जीत नहीं, बल्कि भारत की बदलती राजनीतिक धारा, क्षेत्रीय राजनीति के पुनर्संतुलन और राष्ट्रीय

» पहले नंदीग्राम अब भवानीपुर सीट से दीदी को हराना प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश, नेतृत्व परिवर्तन का संकेत- बंगाल की जनता ने राज्य की राजनीति को नई दिशा देने का फैसला
» पश्चिम बंगाल बदलते राजनीतिक भारत की वह तस्वीर है जहां क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रीय रणनीति, नेतृत्व की छवि और जनमत की दिशा तेजी से बदल रही है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनांनी गोंदिया महाराष्ट्र

दलों के विस्तार की नई कहानी है। कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक पर केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों की भी नजर थी, क्योंकि यह तय होना था कि आखिर उस ऐतिहासिक जनदेश का नेतृत्व कौन करेगा जिसनेबंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अंततः वही हुआ जिसकी राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा थी शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना लिया गया और उनके मुख्यमंत्री बनने का मार्ग औपचारिक रूप से प्रशस्त हो गया। साथियों बात अगर हम इस ऐतिहासिक स्थिति की करें तो यह फैसला केवल एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने की कहानी नहीं है,बल्कि यह उस राजनीतिक यात्रा का परिणाम है जिसमें बंगाल की जनता ने लंबे समय से स्थापित सत्ता संरचना को चुनौती देते हुए एक नए विकल्प पर भरोसा जताया। भाजपा को 293 में से 207 सीटों का स्पष्ट बहुमत मिलना इस बात का संकेत है कि राज्य की राजनीति में व्यापक जनमत परिवर्तन हुआ है। यह जीत सामान्य चुनावी सफलता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बंगाल लंबे समय तक भाजपा के लिए सबसे कठिन राजनीतिक क्षेत्रों में गिना जाता था।



ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री चुना जाना भाजपा की रणनीतिक राजनीति, संगठनात्मक विस्तार और बंगाल में क्षेत्रीय भावनाओं को समझने की क्षमता का सटीक परिणाम माना जा रहा है। साथियों बात अगर हम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा को समझने की करें तो भी इस ऐतिहासिक क्षण को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल रहे अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और तभी से बंगाल की राजनीति में एक बड़े वैचारिक संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। 4 मई 2026 को रिजल्ट आए इस चुनाव में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से हराना केवल चुनौती जीत नहीं बल्कि प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश भी था। यह उस

सबसे उपयुक्त चेहरे साबित हुए। साथियों बात अगर हम विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया की करें तो केंद्रीय गृह मंत्री की विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूदगी ने इस फैसले को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया।यह केवल औपचारिक उपस्थिति नहीं थी बल्कि इससे यह संदेश गया कि भाजपा नेतृत्व बंगाल की सत्ता परिवर्तन को राष्ट्रीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।अमित शाह लंबे समय से बंगाल भाजपा के विस्तार के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया और राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया। विधायक दल की बैठक में उनकी मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में बनने वाली सरकार केवल राज्य की सरकार नहीं बल्कि भाजपा की राष्ट्रीय राजनीतिक परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। साथियों बात अगर हम शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे कई राजनीतिक कारण रहे, इसको समझने की करें तो सबसे पहला कारण उनका मजबूत जनाधार है। वे लंबे समय से बंगाल में भाजपा के सबसे आक्रामक नेताओं में गिने जाते रहे हैं। उनकी राजनीतिक शैली सीधे जनसंपर्क और तीखे राजनीतिक हमलों के लिए जानी जाती है। ग्रामीण बंगाल में उनका प्रभाव विशेष रूप से मजबूत माना जाता है। भाजपा को यह एहसास था कि बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में ऐसे नेता की आवश्यकता होगी जो संगठन और जनता दोनों के बीच समान रूप से प्रभावशाली हों।अधिकारी इस कर्तवीर पर पूरी तरह खरे उतरे।दूसरा महत्वपूर्ण कारण उनका राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक समझ है। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें बंगाल की प्रशासनिक संरचना,स्थानीय सत्ता समीकरण और क्षेत्रीय सामाजिक संरचना की गहरी समझ है। भाजपा के लिए यह अनुभव अत्यंत उपयोगी माना गया

क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने की होगी। तीसरा बड़ा कारण केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका मजबूत तालमेल माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ शुभेंदु अधिकारी के संबंध अत्यंत मजबूत हैं। भाजपा ऐसे राज्य में सत्ता संभालने जा रही है जहां उसे प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर तीव्र चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी ऐसा मुख्यमंत्री चाहती थी जो केंद्र और राज्य के बीच मजबूत सटीकता से समन्वय स्थापित कर सके। साथियों बात अगर हम इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक भावनात्मक पहलू को समझने की करें तो । हाल ही में उनके करीबी सहयोगी की हत्या ने पूरे चुनावी माहौल को प्रभावित किया था। भाजपा ने इसे राजनीतिक हिंसा और लोकतंत्र पर हमले के रूप में प्रस्तुत किया। इससे शुभेंदु अधिकारी के प्रति सहानुभूति की लहर भी बनी, जिसका चुनावी प्रभाव देखने को मिला। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के आरोपों से घिरा रहा है और भाजपा ने इस मुद्दे को अपने चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया। अधिकारी इस राजनीतिक नैरेटिव के केंद्र में रहे।अब जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चर्चा नई सरकार की संरचना को लेकर हो रही है। खबरें हैं कि बंगाल में दो उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं ताकि क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन स्थापित किया जा सके। भाजपा समझती है कि बंगाल की राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। राज्य में लंबे समय तक स्थायी राजनीतिक आधार बनाने के लिए उसे उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, आदिवासी क्षेत्रों, शहरी मतदाताओं और धार्मिक- सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाया होगा। दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा इसी राजनीतिक रणनीति का सटीक हिस्सा मानी जा रही है। साथियों बात अगर हम 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड हाल्ट में हो रहे शपथ

ग्रहण समारोह को समझने की करें तो राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह केवल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश देने का मंच भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें शामिल होने की संभावना ने इस समारोह को राष्ट्रीय का महत्व दे दिया है। भाजपा इस शपथ ग्रहण को बंगाल में नई राजनीतिक शुरुआत के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस राजनीतिक परिवर्तन को गंभीरता से देखा जा रहा है।पश्चिम बंगाल भारत का सांसात्मक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है।बांग्लादेश, नेपाल और पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में राज्य में सत्ता परिवर्तन का असर केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। विदेश नीति, सीमा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर भी इसके प्रभाव पड़ सकते हैं।आर्थिक दृष्टि से भी भाजपा सरकार के गठन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से उद्योग और निवेश के मामले में बंगाल अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया था। भाजपा ने चुनाव अभियान में राज्य कोऔद्योगिक और निवेश केंद्र बनाने का वादा किया था। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार,उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेज बदलाव लाने की होगी।निवेशकों की नजर अब नई सरकार की नीतियों पर होगी। यदि भाजपा केंद्र और राज्य के समन्वय से बड़े निवेश आकर्षित करने में सफल होती है तोबंगाल की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन संभव है।हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। भाजपा को प्रशासनिक ढांचे में विश्वास कायम करना होगा। राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण अत्यधिक गहरा है। तृणमूल कांग्रेस अभी भी मजबूत सामाजिक और राजनीतिक आधार रखती है। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समझदारी बनाए रखने की होगी। यदि सरकार प्रतिशोध की राजनीति से बचते हुए प्रशासनिक सुधार और

विकास पर ध्यान केंद्रित करती है तो यह भाजपा के लिए दीर्घकालिक सफलता का आधार बन सकता है।ममता बनर्जी की राजनीतिक पराजय भी भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। एक समय ऐसा था जब उन्हें भाजपा विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। लेकिन इस चुनाव ने दिखा दिया कि भारतीय राजनीति में कोई भी नेतृत्व स्थायी नहीं होता। जनता समय-समय पर सत्ता परिवर्तन के माध्यम से लोकतंत्र की शक्ति का प्रदर्शन करती है। बंगाल के चुनाव परिणाम इसीलोकतांत्रिक परिवर्तन का उदाहरण है। साथियों बात अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों केविचारों को समझने की करें तो उनका मानना है कि बंगाल में भाजपा की जीत और शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना आने वाले वर्षों की राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। इससे भाजपा को पूर्वी भारत में और अधिक विस्तार का मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। साथ ही विपक्षी दलों की रणनीतियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्षेत्रीय दलों के सामने यह चुनौती होगी कि वे भाजपा के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कैसे करें। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री चुना जाना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यह उस बदलते राजनीतिक भारत की तस्वीर है जहां क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रीय रणनीति, नेतृत्व की छवि और जनमत की दिशा तेजी से बदल रही है। बंगाल की जनता ने एक नया अध्याय लिखा है और अब पूरे देश की नजर इस बात पर होगी कि शुभेंदु अधिकारी इस ऐतिहासिक जनदेश को किस दिशा में ले जाते हैं।

-संकलनकर्ता लेखक - ऋर विश्वेश्वर स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनांनी गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

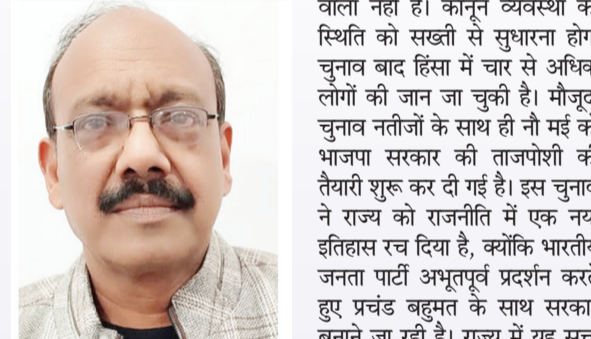
स्वाधीनता का अप्रतिम योद्धा: हल्दीघाटी के महानायक महाराणा प्रताप की अमर गाथा



लेखक-सुनील कुमार महाता

कहते हैं कि जिस राष्ट्र के पास अपने वीरों की गाथाएँ होती हैं, उसका इतिहास कभी पराजित नहीं होता। ऐसे ही एक वीर सपूत हुए हैं-मेवाड़ के रिसोदीया राजवंश से ताल्लुक रखने वाले अदम्य साहसी और स्वाभिमानी वीर महाराणा प्रताप। पाठकों को बताता चर्चू कि 9 मई को राजस्थान में मेवाड़ के गौरव कहलाने वाले, भारतीय इतिहास की शौर्य गाथाओं में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित, स्वाभिमन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले वीर योद्धा और अदम्य साहस के प्रतीक कहलाने वाले महाराणा प्रताप की जयंती को एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह रिसोदीया था, जिनका जन्म 9 मई,1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान में हुआ था, तथा जिनके पिता का नाम महाराणा उदयसिंह तथा माता का नाम रानी जयवंता बाई था। आपके बचपन का नाम कीका था,जो भील समुदाय द्वारा आपको दिया गया था। विश्व प्रसिद्ध स्वामीभक्त घोड़ा चेतक आपको सच्चा साथी था, जिसने हल्दीघाटी के युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, जिससे चेतक का नाम अभी पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। यहां पाठकों को बताता चर्चू कि घायल होने के बावजूद चेतक ने 26 फीट लंबे नाले को एक छलांग में पार कर अपने स्वामी(महाराणा प्रताप) के प्राण बचाए थे। महाराणा प्रताप ने उस दौर में मुगलों का जमकर प्रतिरोध किया, जब उत्तर भारत के लगभग-लगभग सभी राजा मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। पाठक जानते होंगे कि इतिहास के सबसे भीषण माने जाने वाले युद्ध हल्दीघाटी

के युद्ध (18 जून, 1576) में महाराणा प्रताप के पास सीमित सेना थी, जबकि मुगल सेनापति मानसिंह प्रथम के पास विशाल सैन्य बल था। जानकारी मिलती है कि इस युद्ध के बाद ही प्रताप ने छापामार युद्ध (गुरिल्ला वारफेयर) की नीति अपनाई। यहां यह भी गौरतलब है कि हल्दीघाटी का युद्ध वीरता, आत्मसम्मान और अदम्य संकल्प की अमर गाथा है। इतिहास में विवरण मिलता है कि हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान इतनी अधिक संख्या में सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, कि वहां की मिट्टी लाल हो गई थी। युद्ध स्थल के पास आज भी एक तालाब है जिसे रक्त तलाई कहा जाता है। माना जाता है कि युद्ध के दौरान यह तालाब पूरी तरह रक्त से भर गया था। बहरहाल, यहां पाठकों को बता दूँ कि इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध (हल्दीघाटी के युद्ध)को लेकर अलग-अलग मत हैं। सैन्य दृष्टि से मुगल सेना को बढ़त मिली, क्योंकि युद्धभूमि पर उनका नियंत्रण रहा और महाराणा प्रताप को पहाड़ों की ओर गमन करना पड़ा, लेकिन राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से महाराणा प्रताप को पराजित नहीं माना जाता, क्योंकि वे न तो बंदी बने और न ही उन्होंने कभी मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की। गौरतलब है कि युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा और मेवाड़ के बड़े हिस्से को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भीलों ने महाराणा प्रताप के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राणा पूंजा उनके प्रमुख सहयोगियों में थे। गौरतलब है कि इतिहासकार हल्दीघाटी का युद्ध को निर्णायक विजय के बजाय अनिर्णायक युद्ध या मुगलों की सामरिक जीत लेकिन प्रताप की नैतिक विजय मानते हैं। यद्यपि अकबर और महाराणा प्रताप घोर प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन स्वयं अकबर, महाराणा प्रताप की वीरता, स्वाभिमन और संघर्षशीलता का सम्मान करता था। सच तो यह है कि अकबर प्रताप की अदम्य स्वतंत्रता-भावना से प्रभावित बताया जाता है।कहा जाता है कि अकबर ने प्रताप के निधन का समाचार सुनकर दुःख व्यक्त किया था।



लेखक-मनोज कुमार अग्रवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व जीत के बाद जिस तरह की हिंसा और तोड़फोड़ की वारदातों की झड़ी लगी है बेशक वो टीएमसी के दबाई भरे डेड दशक के खिलाफ लोगों की नाराजगी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की सत्ता छिटकने की हताशा की प्रतिक्रिया हो सकता है लेकिन दोनों राजनीतिक दलों को संयम और समझदारी और सदाचार बनाए रखने की जरूरत है। भाजपा को भाजपा बनाए रखने के लिए इस तरह की अराजकता फैलाने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना ही होगा हालांकि यह हिंसा एकतरफा नहीं है जिस तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की बीती कर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें पश्चिम बंगाल वाला नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति को सहसा से सुधारना होगा चुनाव बाद हिंसा में चार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मौजूदा युद्ध नतीजों के साथ ही नौ मई को भाजपा सरकार की ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस चुनाव ने राज्य को राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राज्य में यह सत्ता बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति में एक बड़े वैचारिक और सामाजिक बदलाव की आहट भी है।जितना बड़लंबे समय तक ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की राजनीति का सबसे मजबूत केंद्र माना जाता थाउधर कोलकाता में राज्य के पुलिस डीजीपी ने राज्य में चुनाव परिणाम के बाद आरही हिंसक वारदातों पर उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी जारी की है दो सौ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि चार लोगों की हिंसा में मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार और बुधवार को हिंसा की कई घटनाएँ सामने आई हैं। भाजपा और टीएमसी के पार्टी प्रतिनिधियों ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें पश्चिम बंगाल

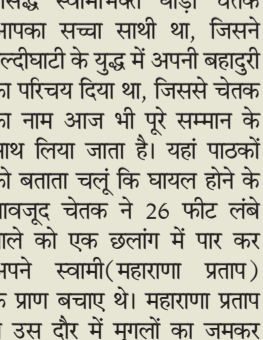
में चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद बुधवार (6 मई) देर रात शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ जिसने कैप पहनी हुई थी, उतरता है और ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की। जिसमें से 3 राउंड रथ के सीने में लगा जिससे उनकी मौत हो गई और उनके ड्राइवर की हालत नाजुक है। गौर करने वाली बात है कि चंद्रनाथ रथ वही शख्स है, जिन्होंने पिछले दिनों चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हुए कई जगह देखे गए थे। जब ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रॉन रूम में दाखिल हुईं, तो चंद्रनाथ रथ बीजेपी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। चंद्रनाथ रथ (42) बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सहायक थे। चंद्रनाथ, शुभेंदु गृह के जिले पूर्वी मितानपुर के चांदीपुर के रहने वाले थे। चंद्रनाथ भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने साल 2019 में शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक के तौर पर काम शुरू किया था, जब शुभेंदु ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल चुनाव की मतगणना से ठीक तीन दिन पहले 30 अप्रैल को जब ममता बनर्जी शाखावत मेमोरियल हाई स्कूल टिखल भवानीपुर के स्ट्रॉन रूम में दाखिल हुईं, तो चंद्रनाथ रथ बीजेपी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। शुभेंदु अधिकारी की गैर-मौजूदगी में वे मतगणना केंद्र के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन का

गाड़ी को हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के सामने लगा दिया। इसके बाद बाइक पर सवार एक हमलावर जिसने कैप पहनी हुई थी, उतरता है और ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की। जिसमें से 3 राउंड रथ के सीने में लगा जिससे उनकी मौत हो गई और उनके ड्राइवर की हालत नाजुक है। गौर करने वाली बात है कि चंद्रनाथ रथ वही शख्स है, जिन्होंने पिछले दिनों चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हुए कई जगह देखे गए थे। जब ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रॉन रूम में दाखिल हुईं, तो चंद्रनाथ रथ बीजेपी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। चंद्रनाथ रथ (42) बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सहायक थे। चंद्रनाथ, शुभेंदु गृह के जिले पूर्वी मितानपुर के चांदीपुर के रहने वाले थे। चंद्रनाथ भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने साल 2019 में शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक के तौर पर काम शुरू किया था, जब शुभेंदु ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल चुनाव की मतगणना से ठीक तीन दिन पहले 30 अप्रैल को जब ममता बनर्जी शाखावत मेमोरियल हाई स्कूल टिखल भवानीपुर के स्ट्रॉन रूम में दाखिल हुईं, तो चंद्रनाथ रथ बीजेपी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। शुभेंदु अधिकारी की गैर-मौजूदगी में वे मतगणना केंद्र के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन का

नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि शुभेंदु उस रात पूर्वी मितानपुर स्थित अपने गृह नगर कांथी के लिए रवाना हो चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि हिंसक घटनाएँ हो सकती हैं। राज्य में तोड़फोड़ और हिंसा की कई खबरें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बयान जारी कर आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोग अपनी पहचान बदलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें बदरिश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जहां उत्तरी 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। वहीं टीएमसी ने कहा कि कोलकाता के बेलेंघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके दो सदस्यों की हत्या हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या तब कर दी गई, जब वह न्यू टाउन में पार्टी की जीत की रैली में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। हावड़ा के उदयनारायणपुर में भाजपा कार्यकर्ता यादव बर का हत्या कर दी गई। टीएमसी के प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने कहा, अब तक हमारे दो कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, एक बीरभूम में और दूसरा कोलकाता में। बीरभूम में, पीडित की पहचान

पार्टी सदस्य अबीर शेख के रूप में हुई, जबकि बेलेंघाटा में टीएमसी कार्यकर्ता बिस्वजीत पुसनायक की हत्या कर दी गई पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये मौतें राजनीति से जुड़ी थीं या नहीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, जिन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बात की, कहा कि कम से कम दो मामले राजनीतिक नहीं थे।अधिकारी ने कहा, शुरुआती जांच से पता चलता है कि हावड़ा में हुई हत्या राजनीतिक नहीं थी। यह निजी दुश्मनी के कारण हुई थी। बेलेंघाटा में, पीडित छत से कूद गया, जब कुछ लोग उसे ढूँढते हुए उसके दरवाजे पर आए और वह भागने की कोशिश कर रहा था। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने कहा, कोलकाता के हंग मार्केट में बुलडोजर से जुड़ी जो घटना हुई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, एक हत्या हुई है, लेकिन यह गैरवार का मामला है। इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा, चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य में तेनात केंद्रीय पुलिस बल को निर्देश दिया है कि वे राज्य में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सुनिश्चित करें।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन है वैचारिक बदलाव का संकेत



लेखक-ललित गर्ग

से बंगाल की राजनीति के भीतर सुलग रहा था। वर्षों तक बंगाल को एक ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां कथित रूप से जाति, धर्म और पहचान की राजनीति नहीं चलती, बल्कि विचारधारा, वर्ग-संघर्ष और बंगालियत्व की राजनीति प्रभावी रहती है। किंतु 2026 के चुनाव परिणामों ने इस स्थापित धारणा को गहराई से चुनौती दी है, यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान में आए परिवर्तन का भी संकेत है। मतदाता अब केवल भावनात्मक नारों या वैचारिक रोमांटिसिज्म के आधार पर मतदान नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य को

भी ध्यान में रख रहा है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता को अनेक विश्लेषक एक प्रकार के 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' के रूप में देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'बंगाली अस्मिता' और 'हिंदू पहचान' के बीच एक वैचारिक द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं को बंगाल की संस्कृति और क्षेत्रीय गौरव का संरक्षक बताया, जबकि भाजपा ने राष्ट्रीयता, हिंदुत्व और सांस्कृतिक चेतना को अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। वास्तव में बंगाल की ऐतिहासिक चेतना कभी संकुचित नहीं रही। यह वही भूमि है जहाँ

से स्वामी विवेकानंद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ ठाकुर और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। 'वंदे मातरम्' का उद्घोष भी इसी भूमि से निकला। इसलिए जब बंगाल में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की चर्चा होती है, तो वह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ भी प्रवेश कर लेता है। भाजपा ने इसी ऐतिहासिक चेतना को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश, रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू धार्मिक प्रतीकों को लेकर जिस प्रकार की राजनीतिक बहसों पिछले वर्षों में सामने आईं, उन्होंने हिंदू समाज के

एक बड़े वर्ग को यह महसूस कराया कि उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ राजनीतिक विवाद का विषय बन रही हैं। परिणामस्वरूप एक बड़ा वर्ग अपनी पहचान के प्रश्न पर अधिक मुखर हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से अल्पसंख्यक वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती रही है। विश्व लगातार यह आरोप लगाता रहा कि ममता बनर्जी सरकार ने संतुलित शासन के बजाय गुटिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। चाहे इमाम भत्ता का मुद्दा हो, धार्मिक आयोगों को लक्ष्य प्रशासनिक नियंत्रण हों या सीमावर्ती जिलों में बदलता जनसांख्यिकीय संतुलन-इन सभी विषयों ने धीरे-धीरे हिंदू समाज

के भीतर असंतोष को जन्म दिया। यह असंतोष केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी था। अनेक लोगों को यह लगने लगा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता का अभाव है। भाजपा ने इसी भावना को राजनीतिक रूप दिया। उसने यह संदेश देने का प्रयास किया कि उसकी राजनीति केवल चुनाव जीतने के नहीं, बल्कि 'सांस्कृतिक सुरक्षा' स्थापित करने की राजनीति है। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान 'जय श्रीराम' जैसे नारे केवल धार्मिक उद्देश्य नहीं रहे, बल्कि वे एक प्रकार के राजनीतिक प्रतिरोध और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक बन गए।



वैभव नंबर 1 पर कायम, पारी में 8 छक्के लगा कूपर कोनोली नहीं निकल पाए उनसे आगे

टूटा डिकॉक का 10 साल पुराना रिकॉर्ड

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के 49वें मैच में पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज कूपर कोनोली ने हैदराबाद के खिलाफ जमकर लड़ाई की और नाबाद 107 रन की शतकीय पारी खेली। कूपर बेशक अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने विन्टन डिकॉक का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपनी पारी में कूपर ने 8 छक्के भी लगाए, लेकिन वो वैभव सूर्यवंशी के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए।

वैभव से पीछे रह गए कूपर कोनोली- कूपर ने हैदराबाद के खिलाफ अपना नाबाद 107 रन की पारी के दौरान कुल 8 छक्के लगाए और वो आईपीएल में अपनी पहली 9 पारियों के बाद सबसे



कूपर ने की प्रभसिमरन की बराबरी

कूपर कोनोली पंजाब किंग्स के लिए 22 साल की उम्र में आईपीएल में शतक लगाने वाले दूसरे बेटर भी बने। इससे पहले पंजाब के लिए 22 साल की उम्र में इस लीग में शतक लगाने का कमाल प्रभसिमरन सिंह ने साल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ किया था। अब कूपर कोनोली ने ऐसा कमाल किया और उनकी बराबरी पर आ गए।

ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। वैभव का रिकॉर्ड टूटने से बच गया और वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। आईपीएल की पहली 9 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है।

छक्के लगाने वाले टॉप-3 बेटर

- 30 छक्के : वैभव सूर्यवंशी
- 28 छक्के : जैक फ्रेंजर मैकगर्क
- 26 छक्के : कूपर कोनोली

कूपर ने तोड़ा 10 साल पुराना रिकॉर्ड

कूपर ने आईपीएल करियर का पहला शतक हैदराबाद के खिलाफ लगाया और वो अब इस लीग में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले विदेशी बेटर भी बन गए। कूपर ने ये कमाल 22 साल 257 दिन की उम्र में किया और उन्होंने विन्टन डिकॉक का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिकॉक इससे पहले आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज थे। उन्होंने ये कमाल साल 2016 में 23 साल 122 दिन की उम्र में आरसीबी के खिलाफ किया था।

सबसे कम उम्र के विदेशी शतकवीर

- 22 साल 257 दिन - कूपर कोनोली बनाम SRH, हैदराबाद, 2026
- 23 साल 122 दिन - विन्टन डिकॉक बनाम RCB, बेंगलुरु, 2016
- 23 साल 153 दिन - डेविड वॉर्नर बनाम KKR, दिल्ली, 2010
- 23 साल 330 दिन - डेविड मिलर बनाम RCB, मोहाली, 2013
- 23 साल 352 दिन - कैमरन ग्रीन बनाम SRH, वानखेड़े, 2023

‘वसीम अकरम से सामने सुपर ओवर में नहीं टिक पाएंगे विराट कोहली’

- 279 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले बॉलर ने किया दावा

नई दिल्ली। विराट कोहली इस युग के बेस्ट क्रिकेटर हैं और ऐसा कई दिग्गज मान चुके हैं। विराट कोहली ने क्रिकेट के हर प्रारूप में खुद को साबित किया और वो आज उस स्थान पर खड़े हैं जहां पहुंचना हर क्रिकेटर के बस की बात नहीं होती है। कोहली से पहले भी कई दिग्गज क्रिकेटर हुए जिन्होंने अपना लोहा मनवाया और किसी दो क्रिकेटर की तुलना करना बेतुका लगता है। आधुनिक पीढ़ी के दिग्गज क्रिकेटर और भारत के अब तक के महानतम क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली के बारे में इयान बिशप ने बात की और जब उनसे विराट कोहली और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम में से किसी एक को विजेता चुनने को कहा गया तब इयान ने वसीम अकरम को कोहली से ऊपर रखा।

अकरम बनाम विराट में किसकी होगी जीत- ईएसपीएन क्रिकइंफो पर एक शो के दौरान वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप (इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 279 विकेट लिए थे) से पूछा गया कि अगर विराट कोहली और वसीम अकरम एक-दूसरे के खिलाफ सुपर ओवर में आमने-सामने हों तो कौन जीतेगा। इसका जवाब देते हुए इयान ने वसीम अकरम को चुना। हालांकि उन्होंने अपने इस चुनाव के पीछे की वजह साफ तौर पर नहीं बताई, लेकिन ऐसा लगा कि गेंदबाजी में अकरम की जिस तरह की महारत थी उसकी वजह से उन्होंने अकरम का चयन किया।

वैभव को खेलता देख आई सचिन तेंदुलकर की याद

... लेकिन माईकल क्लार्क ने कहा- टेस्ट के लिए जल्दबाजी न करने की चेतावनी भी दी

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। माइकल क्लार्क ने कहा है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में किसी खिलाड़ी को इस तरह खेलते पहले नहीं देखा। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन ने हर किसी को हैरान कर दिया है।



बातचीत के दौरान माइकल क्लार्क ने वैभव सूर्यवंशी के आसपास बन रहे माहौल की तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के शुरूआती दिनों से की। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इतनी जल्दी वैभव सूर्यवंशी से टेस्ट क्रिकेट में बड़े चमत्कार की उम्मीद करना सही नहीं होगा।

माइकल क्लार्क ने कहा, ‘‘खैर, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने किसी 15 साल के बच्चे को ऐसा करते हुए नहीं देखा।’’ माइकल क्लार्क ने हालांकि, वैभव के मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाने की चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘आप जानते हैं दोनों बहुत अलग खिलाड़ी हैं और हां आप तुलना नहीं कर सकते। जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया आए थे और उनके बारे में जो चर्चा थी, उस समय सच में वैसी चर्चा थी। मुझे लगता है कि वह 16 साल के थे। हां, 16 के ही थे। और वह चर्चा उन्होंने अपनी काबिलियत से हासिल की थी।

उनकी वह विरासत आज भी सबके सामने है।’’ वैभव सूर्यवंशी ढ़क्क सीजन के सबसे ज्यादा चर्चा वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। उनकी निडर बल्लेबाजी और शांत स्वभाव ने भारत के बाहर भी लोगों का ध्यान खींचा है। वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 10 मैचों में 237.64 के स्ट्राइक रेट से 404 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक और एक शतक शामिल है। इस युवा खिलाड़ी की तेजी से हुई तरक्की ने इस बात को लेकर उत्सुकता जगा दी है कि वह वह भविष्य में क्या बन सकते हैं, लेकिन माइकल क्लार्क ने जोर देकर कहा कि इस चर्चा को वर्तमान पर ही केंद्रित रखना चाहिए।

माइकल क्लार्क ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि कोई यह कह रहा होगा कि वह सीधे टेस्ट क्रिकेट में जाकर तुरंत ही महान खिलाड़ियों में से एक बन जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से वह खेलते हैं, अभी मैं जो देख रहा हूँ, वह इस फॉर्मेट के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है।’’



इसके साथ माइकल क्लार्क ने यह भी साफ किया कि इतनी कम उम्र में इस तरह का प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से उन्हें क्रिकेट की दुनिया में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करने की राह पर आगे बढ़ता है।

व्यापार

पीएफ पर 34% ब्याज! प्राइवेट ट्रस्ट अब नहीं दे पाएंगे भारी-भरकम इंटररेस्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने उन कंपनियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है जो अपना योगदान खुद के ट्रस्ट के जरिए संभालती हैं। अब इन कंपनियों के लिए हर साल होने वाले अनिवार्य ऑडिट की जगह रिस्क-आधारित सिस्टम लागू किया जाएगा। साथ ही, ये ट्रस्ट अपने कर्मचारियों को दर से 2% से ज्यादा ब्याज नहीं दे सकेंगे। नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी बिकने या मर्ज होने पर भी उनका पीएफ ट्रस्ट का स्टेटस खत्म नहीं होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने हाल ही में इन नियमों को मंजूरी दी है।



कूल ट्रस्ट तब 34% जैसा भारी-भरकम ब्याज देने लगते थे जब उनके सदस्यों की संख्या बहुत कम रह जाती थी। ऑडिट के मामले में अब ईपीएफओ केवल उन्हीं कंपनियों या ट्रस्ट की जांच करेगा जिनमें जोखिम ज्यादा होगा। या जो नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे। जो

कंपनियां नियम मान रही हैं, उनका हर साल ऑडिट करना जरूरी नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ती है या उसे खरीदती है तो भी उसका तहत ‘ट्रस्ट प्रात’ दर्जा बरकरार रह सकेगा। एक सीनियर अधिकारी ने ध्ध्रज को बताया कि

भारत में करीब 1,000 से 1,200 बड़ी कंपनियां, और प्राइवेट संस्थान हैं जिन्हें छूट मिली हुई है। ये कंपनियां एकत्र 1952 की धारा 17 के तहत अपना ट्रस्ट खुद चलाती हैं। हालांकि, शर्त यह होती है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को स्कीम के बराबर या उससे बेहतर फायदे देने होंगे हैं। कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से या कोर्ट के आदेश पर ही इस छूट (एजेंजेशन) को खत्म कर सकती है। अगर कोई कंपनी अपना ट्रस्ट बंद करती है या छूट छोड़ती है, तो उसे अखबारों में पब्लिक नोटिस देना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारियों का हक सुरक्षित रहे। साथ ही, बंद होने के वक्त उन सभी खातों को (जिनकी केवाईसी नहीं हुई है या जो बंद पड़े हैं) को ट्रॉसफर करना होगा, ताकि पैसों का गलत इस्तेमाल न हो सके। इन बदलावों का मकसद सरकारी निगरानी को मजबूत करना।

दो राज्यों से आईटी डिपार्टमेंट ने जुटाए 20,000 करोड़, एमएस धोनी सबसे बड़े टैक्सपेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। 2025-2026 के दौरान झारखंड और बिहार से इनकम टैक्स विभाग का कुल कलेक्शन लगभग 20,000 करोड़ रुपये रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी दोनों राज्यों को मिलाकर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत टैक्स देने वाले शख्स रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इनकम टैक्स के प्रधान मुख्य आयुक्त (बिहार-झारखंड) डॉ. डी. सुधाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार और झारखंड से कुल कलेक्शन लगभग 20,000 करोड़ रुपये रहा। इसमें से 12,000 करोड़ रुपये सिर्फ झारखंड से जमा हुए।’

धोनी सबसे बड़े टैक्सपेयर: उन्होंने बताया कि कुल कलेक्शन का लगभग 70 फीसदी हिस्सा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (इडएस) के जरिए मिला। राव ने कहा, ‘पिछले वित्त वर्ष के दौरान बिहार और झारखंड को मिलाकर एमएस धोनी सबसे ज्यादा व्यक्तिगत

टैक्स देने वाले व्यक्ति थे।’ हालांकि, उन्होंने धोनी के नेट टैक्स रिटर्न की जानकारी देने से परहेज किया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कॉर्पोरेट जगत में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सीएमपीडीआई सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनियों में शामिल थीं। राव ने कहा, ‘पिछले वित्त वर्ष के दौरान, भारी बाहिर की वजह से खनन गतिविधियों पर थोड़ा असर पड़ा था। इसका असर कलेक्शन पर भी दिखा। हमें उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा।’

उन्होंने आगे बताया कि बिहार और झारखंड में लगभग 5.5 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट को लेकर बैठक इससे पहले, राव ने इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को लेकर एक बैठक की। यह एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा।

प्रतीक्षा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं

जिस सरकारी बैंक में कभी 65 महीने में टॉयलेट करती थीं साफअब वहीं एजीएम

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रतीक्षा टॉयलकर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वह मुंबई की रहने वाली हैं।



भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में कभी उन्होंने सफाईकर्मी के तौर पर काम किया। टॉयलेट और बैंक के फर्नीचर की सफाई की। सिर्फ 65 रुपये महीने की पगार पर वह ये सभी काम करती थीं। फिर आगे चलकर उसी बैंक में प्रतीक्षा असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन गईं। 17 साल की उम्र में शादी। फिर 20 साल की उम्र में पति का सिर पर से साया उठ जाने तक, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सहा है। जिस मुकाम तक प्रतीक्षा आज पहुंची हैं, वह उनकी कड़ी मेहनत और लगन के कारण प्रयत्निक दया। आखिर यहां

प्रतीक्षा टॉयलकर की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। प्रतीक्षा की शादी 17 साल की उम्र में सदाशिव कडू से हो गई थी। माता-पिता की आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा भी पूरी नहीं कर पाई थीं। सदाशिव मुंबई में एसबीआई में बुकबाइंडर के तौर पर काम करते थे। दुख की बात यह है कि जब यह जोड़ा अपने गांव जा रहा था, तभी एक दुर्घटना में सदाशिव की मौत हो गई। इससे 20 साल की उम्र में ही प्रतीक्षा को अपने गुजारे के लिए संघर्ष करना पड़ा।

एसबीआई में सफाईकर्मी का किया काम: शिक्षा की कमी के कारण प्रतीक्षा के लिए ठीक-ठाक नौकरी खोजना काफी मुश्किल था। परिवार का पेट पालने और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें एसबीआई में सफाईकर्मी के तौर पर काम करने पर मजबूर होना पड़ा। टॉयलेट और बैंक के फर्नीचर की सफाई करके वह महीने के लगभग 60-65 रुपये कमाती थीं। साथ ही अपने बेटे की देखभाल करती थीं। यही नहीं, दूसरे छोटे-मोटे काम भी करती थीं। प्रतीक्षा ने दिन-रात एक कर दिया और अपने बेटे का पेट पालने के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मेहनत की। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे संघर्ष और जीत के कई पड़ाव होते हैं। प्रतीक्षा की कहानी भी इससे अलग नहीं थी।

खाड़ी युद्ध ने बिगाड़ा शाही शादियों का बजट, लेकिन भारत के लिए आया आपदा में अवसर

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव का असर अब भारतीय शादियों के बजट पर साफ दिखने लगा है। वेडिंग्स एंड इवेंट्स के फाउंडर्स मोहित वर्मा और तमन्ना मेहता का कहना है कि विदेशों में होने वाली शादियों का बजट करीब 20-25% बढ़ गया है। देश के भीतर होने वाली शादियों के खर्च में भी 10-15% का उछाल आया है। इवेंट्स की डायरेक्टर आंचल कोचर का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर उन शादियों पर पड़ा है जो विदेशों में होनी थीं। तनाव की वजह से पश्चिम एशिया का हवाई रास्ता प्रभावित हुआ है। टैमरिंड ग्लोबल की वीपी अंजलि तोलानी का कहना है कि लग्जरी शादियों में इस्तेमाल होने वाले बाहर से मंगाए गए फूल, प्रीमियम खाने-पीने की चीजें और सजावट के ख़ास सामान की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। शिपिंग का खर्च बढ़ने और सामान आने में देरी की वजह से इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। द वेडिंग कंपनी के हरिकृष्णन दिनेश ने बताया कि कई मामलों में प्लानर्स को चीन जैसे बाजारों से महंगा सामान मंगाना पड़ रहा है। परिवार अब फूंक-फूंक कर पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ वेडिंग्स ने कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे



वेडिंग प्लानर्स का मुनाफा कम हो गया है और उन पर काम का दबाव बढ़ गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमीर लोग तो इस बढ़ी हुई लागत को झेल पा रहे हैं। कई भारतीय वेडिंग्स जिन्होंने खाड़ी देशों में अपना काम जमाया था, वे अब वापस भारत की ओर ध्यान दे रहे हैं।

मिडल क्लास

इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। आंचल कोचर के मुताबिक, कम बजट वाले लोग अब फंक्शन कम कर रहे हैं, मेहमानों की लिस्ट छोटी कर रहे हैं और सफर का खर्च बचाने के लिए घर के पास वाले वेन्यू ही चुन रहे हैं।

भारत का फायदा

सारी उथल-पुथल के बीच भारत के लोकल बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर भी है। खाड़ी देशों में होने वाली बहुत सी शादियां अब भारत में शिफ्ट हो रही हैं। अंजलि तोलानी ने बताया कि राजस्थान, गोवा, केरल और देहरादून जैसे भारत के लग्जरी ठिकानों के लिए बुकिंग में अचानक तेजी आई है। इन जगहों पर भारी डिमांड की वजह से होटलों और वेन्यू की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 35-40% तक बढ़ गई हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद जकी हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।

संपादक :- सैयद जकी हैदर - हेड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कर्नोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक्रवी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM)

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।

नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)